(ख) यदि हां तो उक्त रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कृषि उद्योग के विकास के लिये क्या ठोस कदम उठाये हैं और इसके क्या परिणाम रहे ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) उद्योग मंत्रालय ने कोई रिपोर्ट नहीं तैयार की है क्योंकि इसमें भारत में ग्रामीण उद्योगीकरण पर बातचीत करने के लिए 1985 के अन्त में भारतीय विशेषज्ञों के शिष्टमण्डल को सोवियत रूस नहीं भेजा था ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

कुटीर व लघु उद्योग

1653. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार आर्थिक सामाजिक और नैतिक दृष्टि से कुटीर व लघु उद्योगों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग मानती है ;

(ख) यदि हां, तो कुटीर व लघु उद्योगों के गांवों से तेजी से गायब होने तथा शहरों में आश्रय लेने के क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ; और

(घ) सरकार किस प्रकार के कुटीर व लघु उद्योगों को गांवों में स्थापित करने का विचार रखती है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) जी, हां । 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प तथा बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में देश के भीतर औद्योगिक विकास के सामाजिक उद्देश्यों पर बल दिया गया है । इस औद्योगिक विकास में उद्योगों का क्षेत्रीय छितराव, ग्रामीण तथा लघु उद्योगों का संवर्धन और एकाधिकार की रोकथाम करना सम्मिलित है ।

(ख) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर तथा लघु उद्योगों की स्थापना करने की दिशा में काफी प्रगति हुई है ।

(ग) लघु उद्योगों के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है । फिर भी विभिन्न प्रोत्साहन रियायतें और केन्द्रीय निवेश राजसहायता रियायती वित्त आदि जैसी तकनीकी और अन्य सुविधाएं विपणन मशीनों व उपकरणों की किराया खरीद प्रबंध व तकनीकी प्रशिक्षण और लघु उद्योग सेवा संस्थानों औजार कक्षों, फील्ड टैस्टिंग केन्द्रों और खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों आदि के माध्यम से जांच संबंधी सुविधाएं देकर केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता देती है ।

(घ) स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों आदि की उपलब्धता के आधार पर राज्य सरकारें ग्रामों में उपयुक्त उद्योगों की स्थापना का प्रोत्साहन देती हैं ।

Cracks in Sagar Samrat drilling *rig* of Oil and Natural Gas Commission

1854. SHRI V. NAEAYANASAMY: Will the Minister of **PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:**

(a) whether it is a **fact that Sagar** Pragati jack-up rig used **by ONGC** suffered major cracks in its hull **and** leg in April, 1985 and it was sent to Dubai for repair work and **the** said repair work is being delayed **by** the **attitude of** the **Government ii** not attending the same **in quick** succession;

(b) whether it is a fact that the Government has lost more than Rs. 30 crores due to the slackness; and

(c) whether the Government is taking any action against the officials who wer« responsible for the said loss?

THE MINISTER OP **STATE OP** THE **MINISTRY OP PETROLEUM** AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM **DUTT):** (a) **Cracks** were **detected in** the legs of ONGC'si jack-up

rig Sagar Pragati in April, 1985. The »g suffered some further damage to its hull and legs during its journey to Dubai for purposes of dry docking on account of encountering severe cyclonic conditions. The contract for fabrication and installation of the legs of the rig has been, awarded to a Japanese Arm in September, 1986.

(b) No, Sir. . (c) Does not arise.

Proposals. for setting up cement factories in Gujarat,

1855. SHRI RAMSINGHBHAI PATAL1YABHAI RATHVAKOLL Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state;

(a) Whether Government have received any proposals for setting up of cement factories in Gujarat during the last 3 years;

(b) if so, what are the details thereof indicating their estimated cost projected capacity and the sector in which they are to be set up «nd how many of such applications are for the establishment of cement factories in Adivasi and backward areas;

(c) what action has been taken in each case;

(d) how many cement factories have already been established and set up during these years and what is the yearly production of each factory; and

(e) whether the production of cement in Gujarat is sufficient to meet the demand of that State; if so, how this cement is distributed?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT oF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (c) Out of the total of 24 Industrial Licence applications received during the last three yeara (1983-85), for setting up of Cement plants in various places in **the** State of Gujarat, 11 applications had been approved and letters of intent wcra issued. Details of applications received, their location, capacity, investment proposed and decision in each case, are given in **the** Statement below.

. (d) During the above **three yean,** 12 new cement factories in **Gujarat** had gone into production. Their pro duction during the last three year was as follows;

(Production in lakh tonnes)

Year	No. of factories	Production of new factories	Total production in the State
1983	1	2·78	21·05
1984	3	0·11	21·2
1985	8	0·24	25·5

(e) Total production of cement la Gujart during 1985 was 29. 50 lakh tonnes, out of which a little over about 12 lakh tonnes was taken as levy obligation and the rest was sold by the factories as non-levy cement. While the present demand of cement in Gujarat has not been assessed, no complaints about shortage of cement in Gujarat have been received.